

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 09/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/09

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय-502,टावर-ए,
पेनिन्सूला बिजनेस पार्क, सेनापाली
बापत मार्ग, लोअर पारेल मुम्बई
400013 शाखा कार्यालय
31-1,लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, न्यू बनारस
पावर हाउस के सामने के सामने
एस.बी.आई. के पास इण्डस्ट्रीयल
एस्टेट जोधपुर 342003

1. श्री महेश कुमार निवासी रावल निवासी
पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी
जिला बांसवाडा 327022 (ऋणी)
2. श्री हर्षित जैन निवासी रावल निवासी
पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी
जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी)
3. श्री विनोद कुमार जैन निवासी रावल
पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी
जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी)
4. श्रीमती सुनीता एस. निवासी रावल
पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी
जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 02-08-2023

प्राधिकृत अधिकारी केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1-

श्री महेश कुमार निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022

(ऋणी) 2- श्री हर्षित जैन निवासी रावल निवासी पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला

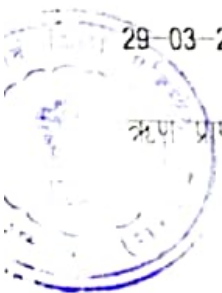
बांसवाडा 327022 (सहऋणी) 3- श्री विनोद कुमार जैन निवासी रावल पाटीदार मौहल्ला समगडा,

तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी) 4- श्रीमती सुनीता एस. निवासी रावल निवासी

पाटीदार मौहल्ला समगडा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा 327022 (सहऋणी) ने वित्तीय आस्था से दिनांक

29-03-2021 को राशि रुपये 33,11,618 (अक्षरे तैतीस लाख ग्यारह हजार छ सौ अठ्ठारह रुपये मात्र) का

ऋण प्राप्त किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा, (राज.)

व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05-04-2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 16-05-2022 को कुल बकाया राशि 3464339 रु. (चौतिस लाख चौसठ हजार तीन सौ उन्चालीस रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय व्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्वोरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति संख्या 1 प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण सम्पत्ति सं.1 मकान वाके खसरा नंबर 3345/810, गांव समागडा, ग्राम पंचायत आसोडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) 327022 पर स्थित मकान जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 97.77 वर्ग गज है, जिसके पूर्व में मणीलाल जी का प्लॉट, पश्चिम में मोगजी का मकान, उत्तर में डामर रोड, दक्षिण में शंकरजी का मकान है। अचल सम्पत्ति संख्या 2 जिसका विवरण सम्पत्ति सं.2 मकान वाके खसरा नंबर 7258, गांव पालोदा, ग्राम पंचायत आसोडा, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) 327022 पर स्थित मकान जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग 97.77 वर्ग गज है, जिसके पूर्व में पाटीदार जी का प्लॉट, पश्चिम में गढी पालोदा डामर रोड, उत्तर में टेलर जी का मकान, दक्षिण में आबादी भूमि है। को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2016 के अनुसार प्रार्थी केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण

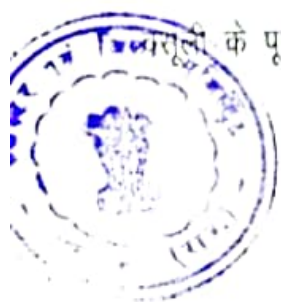
सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

कलक्टर एच जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 20-05-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नोटिस बाद चरपा होकर तहसीलदार गढी की वाद तामील रिपोर्ट के साथ दिनांक 06.07.2023 को प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे है। दिनांक 19.07.2023 को भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, न्यायहित में अवसर दिया जाकर सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 02.08.2023 नियत की गई।

आज दिनांक 02.08.2023 को भी अप्रार्थीगण सं 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थीगणों को बार बार रुक रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगणों को दिनांक 29-03-2021 को राशि रुपया 33,11,618 (अक्षरे तैतीस लाख ग्यारह हजार छ सौ अठ्ठारह रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05-04-2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 16-05-2022 को कुल बकाया राशि 3464339 रु. (चौतिस लाख चौसठ हजार तीन सौ उन्चालीस रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की



डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज
जांसीवाड़ा (राज.)

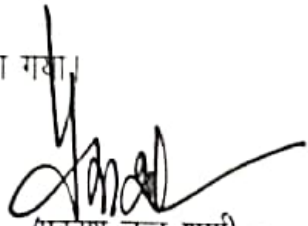
एक्ट 2002 के तहत दिनांक 20-05-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वित्तीय संस्था द्वारा दिनांक 29-03-2021 को राशि रूपया 33,11,618 (अक्षरे तैतीस लाख ग्यारह हजार छ सौ अठ्ठारह रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05-04-2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 20-05-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

अतः सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा। तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात केप्री ग्लोबल केपीटल लिमिटेड को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।



निर्णय आज दिनांक 02-08-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
क्लर्क एवं जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)